

SHRI TINDIVANAM G. VENKAT-RAMAN: Another thing I would like to know is whether the eye-witness have been examined at all in this case. So, far nothing has been said in this regard. With regard to the investigation, so many columns have been written in the papers. How far this is going on and whether the investigation is going on rightly is the question. Our Home Minister has said so many things. I am only putting all these very important aspects before him for his consideration. That is why I said certain unravelled mysteries are there and these points should be investigated in the best interest of the case.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) :
उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने आपसे अनुरोध किया था।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is not zero hour. We are taking up only listed Special Mentions. Were you permitted by the Chair?

श्री ईश दत्त यादव : चेयर से परमिशन तो नहीं मिली थी लेकिन ...

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : फिर कैसे ?

श्री ईश दत्त यादव : पीठासीन अधिकारी श्री बेबी थे। उनसे मैंने अनुरोध किया था तो उन्होंने कहा कि स्पेशल मेंशन के बाद आपको समय दे दिया जाएगा लेकिन उस समय लंच हो गया फिर प्राइवेट मैम्बरज का समय था।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The House is meeting on Monday.

श्री ईश दत्त यादव : गृह मंत्री जी बैठे हैं, मामला गम्भीर है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : गृह मंत्री जी लीडर हैं हाऊस के। वे आपको सुनेंगे।

Clarifications on the Statement regarding drought situation in the country

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) :
उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में बारिश की कमी के कारण जो कृषि की हालत है उसके बारे में मंत्री जी का जो बयान आया उस के संबंध में मैं उनसे कुछ स्पष्टीकरण पूछना चाहती हूँ। इन्होंने पेज नम्बर 2 में पैरा 8 और 9 में कुछ बातें कही हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कितनी बारिश हुई है और कितनी धान की खेती हो सकी है। पैरा नम्बर 9 में उन्होंने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इसका मुकाबला करने के लिए क्या कुछ करना शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि बिहार में 51,73,000 हेक्टेयर जमीन में धान की खेती होती है। गेहूं की खेती 18,73,000 हेक्टेयर जमीन में होती है। 8,74,000 हेक्टेयर में दूसरी रबी की खेती होती है तथा दूसरे सीरियल 1,60,000 हेक्टेयर जमीन में होते हैं। आप यह देखेंगे कि पिछले साल इसी समय जुलाई के अंत में और अगस्त के शुरू में 36 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई हो चुकी थी और इस साल अभी तक केवल 11 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई है। बिहार के 39 जिले हैं जहां धान की खेती होती है। इसके साथ एक बात और है। एक तो बारिश नहीं हुई और दूसरे एग्जोर्ट इरीगेशन जहां से उपलब्ध है जैसे सोन केनाल सिस्टम जो 117 साल पुराना है जहां से सेंट्रल बिहार के सभी स्थानों पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है वहां पानी की भी कमी हो गई है। बाणसागर एग्रीमेंट 1973 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच में हुआ था जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन होगा और कम से कम पांच हजार क्युसेक पानी रिहान और सोन से बिहार को पानी मिलेगा। लेकिन अब सिंगरौली में भी बिजली का कारखाना बंद गया है। वहां विद्युत उत्पादन के लिये पानी तो दिया जा रहा है और शहर में भी पीने के पानी और अन्य कारणों में उसका इस्तेमाल

[श्रीमति कमला सिन्हा]

हो रहा है। नतीजा यह है कि बिहार को सोन कैनल सिस्टम में पानी नहीं मिल रहा है। सोन कैनल सिस्टम सुख रहा है। सारे सेंट्रल बिहार के खेतों में पानी नहीं है। एक तो यह स्थिति हो गयी है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार तत्काल सोन कैनल सिस्टम को बाणसागर योजना के एग्रीमेंट के मुताबिक न्यूनतम साढ़े पांच हजार क्यूसेक्स पानी उपलब्ध करायेगी? नहीं तो मध्य बिहार में जहां सोन नहर से सिंचाई होती है जिसे अनाज का भंडार कहा जा सकता है, वहां सरप्लस उत्पादन होता है, वहां भी अगर खेती मारी गयी तो फिर बिहार में हाहाकार मच जायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं। आपने कहा है :

"...steps for creating an awareness among farmers for taking up alternate crops. Steps have been taken to ensure uninterrupted supply of power..."

यह बिहार के बारे में आपने कहा है "अनइंटरप्टेड सप्लाई आफ पावर किसानों को दिया जायेगा।" मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहती हूं कि बिहार की टोटल इंस्टाल्ड कैपेसिटी साढ़े 13 सौ मेगावाट है और जनरेशन होता है 3-4 सौ मेगावाट। आधे कल कारखाने बन्द पड़े रहते हैं। दामोदर वैली कारपोरेशन के जो बिजली के कारखाने हैं वहां से हमको बिजली मिल नहीं पाती है। यह स्थिति है। सभी गांवों में बिजली भी उपलब्ध नहीं है। बिजली की लाइन अभी तक नहीं जा पाई है। तो कैसे काम हो पायेगा। क्या इसके लिये आप आल्टरनेट अरेंजमेंट के रूप में डीजल को उपलब्ध करायेगी, क्या पर्याप्त मात्रा में डीजल की उपलब्धि होगी?

तीसरा प्रश्न मेरा बिहार के मुताबिक यह है कि सोन नहर सिस्टम से उत्तर प्रदेश और सिंगरौली में जो बिजली

उपलब्ध होती है उसमें से क्या बिहार को 15 सौ मेगावाट बिजली तत्काल दी जायेगी।

ये तो मैंने बिहार के संबंध में प्रश्न पूछे हैं। अब मैं कुछ प्रश्न वेस्टर्न यू०पी० और हरियाणा के बारे में पूछना चाहूंगी जिनके बारे में संजी महोदय को अच्छी तरह से जानकारी होगी। गन्ने की फसल की खेती वहां ज्यादा होती है। पानी की कमी के कारण गन्ने की खेती सुख रही है जो थोड़ी बहुत बची भी है उसमें कीड़े लग रहे हैं। क्या सरकार इस पर एरियल स्प्रे करायेगी और सस्ते दामों पर किसानों को कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करायेगी?

दूसरा प्रश्न उत्तर प्रदेश के मुताबिक है। धान की रोपाई लगभग 40 प्रतिशत हो पाई है। इसलिये क्या आल्टरनेट खेती के रूप में कपास और गन्ने की खेती पर सरकार विशेष रूप से ध्यान देकर इनको लगवायेगी?

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि फसल की पैदावार कम होने से किसान को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार कैसे करेगी। कम से कम सिंचाई दरों में और भू-राजस्व आदि में छूट देने का विचार क्या सरकार कर रही है और क्या कम से कम इस वर्ष उर्वरक और कीटनाशक सभी दवाइयों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है?

चौथा प्रश्न यह है कि बारिश की कमी के कारण वाटर टेबुल नीचे चला गया है। वाटर टेबुल नीचे जाने के कारण लिफ्ट इरीगेशन नहीं हो पा रही है। इस स्थिति में लिफ्ट इरीगेशन के लिये डीप बोरिंग करके टयबवेल्स लगाने का प्रस्ताव क्या सरकार रखती है? क्या तुरन्त इस काम को करायेगी? धन्यवाद।

श्री छोद् भाई पटेल (गुजरात) :
वाइस चेयरमैन महोदय, आपके माध्यम से मैं सिर्फ दो तीन छोटी सी बातें

पूछना चाहूंगा । ड्राउट सिचुएशन में फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है तो फार्मर्स को अब 24 घंटा बिजली देने के बारे में आपने क्या कोई कार्य योजना बनाई है ? दूसरी बात यह है कि जो खराब ट्यूबवेल्स हैं, उनकी मरम्मत करने के लिये क्या कोई योजना तैयार की गई है ?

जो नहरें चलती हैं, तो वह रात-दिन चलाई जायेगी या नहीं, क्योंकि पानी जो झील में है, पानी तो अभी है आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक, तो यह नहरें चलेगी ? मगर जो छोटी-छोटी नहरें हैं, इनमें बहुत घास होता है और उससे पानी बहने में रुकावट होती है । तो क्या उसकी सफाई की जायेगी या नहीं ? यदि सफाई करेंगे, तो फार्मर्स को ज्यादा पानी मिल पायेगा और वाटर मैनेजमेंट के मुताबिक पानी का बचाव भी ज्यादा होगा ।

इसी तरह हमारा जो फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उससे संपर्क किया है या नहीं ? इस इंस्टीट्यूट के जरिये इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं ?

हमारे देश में ड्राई फार्मिंग भी है, तो ड्राई फार्मिंग इंस्टीट्यूट से संपर्क करके उसके जरिये सूखाग्रस्त एरिया में किस-किस प्रकार की क्राप्स हम कम पानी में पैदा कर सकते हैं, इसके बारे में क्या किया जा रहा है ?

इसके अलावा खास करके मवेशियों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है । तो इस पशुधन को बचाने के लिये फाडर के लिये हमने अभी क्या योजना बनाई है ? जहां ग्रीन एरियाज हैं और जहां फाडर की उपलब्धि ज्यादा है, वहां पशुधन की माइग्रेशन करने के बारे में हमने कुछ सोचा है कि नहीं ?

मुझे लगता है कि जब ड्राउट सिचुएशन देश में होती है, तब छोटे फार्मर्स को बहुत हानि पहुंचती है । तो छोटे, मार्जिनल फार्मर्स को ट्यूबवेल के बारे में, बिजली

के बारे में, बीज के बारे में और अभी-अभी जो शुरू-शुरू में बीज बोया गया था, वह तो खराब हो गया है । तो उनको दूसरा बीज दिया जायेगा और वह भी सन्सिडराईज्ड सीड दिया जायेगा या नहीं ?

इसी प्रकार जो फार्मर्स को खाद पर दी जाने वाली सन्सिडरी को हमने नये बजट में विद्वद्धा कर लिया है और इसके मूल्य में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो क्या इस मूल्य वृद्धि को समाप्त किया जायेगा ?

मान्यवर, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे केवल दो-तीन प्रश्न पूछने हैं । जैसा कि मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल राजस्थान यहां पर जो वर्षा कम हुई, उसका प्रभाव पड़ा है और उसके फलस्वरूप यहां पर सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हुई ।

दूसरा कारण यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो जलाशय हैं, रेजरवायर हैं, उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है ।

तीसरा, यह बतलाया गया है कि मानसून की अनियमित प्रवृत्ति के प्रकाश में कृषि मंत्रालय ने पीने के पानी, चारा और बिजली की आपूर्ति आदि से निवृत्ते हेतु 12 जुलाई 1991 को उत्तरी और पश्चिमी राज्यों को पुनः सलाह दी थी । उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे प्रभावित होने वाले संभावित लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए परियोजनाओं के ढांचे तैयार करें ।

तो मैं जानना चाहता हूं कि 12 जुलाई को जो सलाह दी गई थी कृषि मंत्रालय की ओर से, जिन राज्यों के संबंध

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

में सलाह दी गई थी, उनके यहां से भी कोई फीड बैक कृषि मंत्रालय को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ?

विशेषकर टेस्ट वर्क चालू करने के लिए यह राज्यों में क्या योजना शुरू करने जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बजराम जाखड़) : कौनसी योजना ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : नोजगार प्रदान करने के लिए टेस्ट वर्क ।

इसके साथ ही जो नुकसान हो चुका है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी ? क्या कोई मुआवजा देने का प्रस्ताव कृषि मंत्रालय की ओर से है ? दूसरा जो यह सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं जहां आलरेडी नुकसान हो चुका है, जहां बुवाई में देरी हुई है तो वहां जो पक्कों के ऊपर लगान की बसूलो या हमारे उत्तर प्रदेश में एक पम योजना का टैक्स लगता है, इसको मुआफ करवाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को सलाह दी जाएगी ?

अंत में, मेरा प्रश्न यह है कि जो बजट अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया है इसमें उर्वरक के सिलसिले में जो सब्सिडी में कटौती की गई है और उसकी कीमत में 40 प्रतिशत वृद्धि की गई है तो कम से कम यह जो सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए, यहां दिल्ली की सरकार, जो 40 परसेंट उर्वरकों के दाम में वृद्धि की गई है, उसको समाप्त करेगी ?

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत वक्तव्य सूखे की स्थिति के संबंध में दिया है, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के संबंध में, वैसे तो सभी राज्यों का थोड़ा-बहुत संकेत रूप से उल्लेख किया गया है विशेष रूप से सूखे और वर्षा के संबंध में जो मौसम विज्ञान विभाग है उसका बहुत बड़ा महत्व

है, भूमिका है । उस भूमिका के आधार पर अगर सही ढंग से काम हुआ, जो आज का सारा वैज्ञानिक ढांचा है, जिस तरह से जो सारे मिशन चलते हैं तो उसके आधार पर अगर सही समय पर सूचना हो जाए तो बहुत कुछ उस स्थिति और परिस्थिति का मुकाबला पूरे देश के लोग भी कर सकते हैं, किसान भी कर सकते हैं और सरकार की तरफ से पहले से ही कदम उठाए जा सकते हैं । इस सिलसिले में पैरा 2 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 27 मई, 1991 को दक्षिण पश्चिम मौसम की यह भविष्यवाणी की गई थी कि मौसम में संपूर्ण देश में वर्षा की मात्रा दीर्घवर्ध औरत महत्व की 94 होगी, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को और भी सक्षम बनाने के लिए जो दूसरे देशों में और भी इस प्रश्न पर इस संबंध में जो विज्ञान आगे बढ़ गया है उसका उपयोग करते हुए क्या उसको आधुनिक बनाने का काम करेंगे ताकि वह पहले से ही, आपने मई को बताया, हो सकता है कि उसके बाद और भी कोई स्थिति आए कि सही जानकारी पूरे देश को, चाहे पानी पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, मौसम किस तरह का होगा, उसके बारे में जानकारी हो सकेगी । दूसरी बात यह है कि यह बात तो आपने अपने उत्तर में दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में, सब जगहों पर कितनी फसल का नुकसान हुआ है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मैंसे आपने पृष्ठ 3 पर पैरा 8 में लिखा, हरियाणा का जिक्र करने के बाद, कि उत्तर प्रदेश में ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों की फसलों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है उत्तर प्रदेश में सामान्य चावल क्षेत्र का केवल 40 प्रतिशत क्षेत्र में ही प्रतिरोपण हुआ है । मुझे ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार ने और कृषि विभाग ने माननीय मंत्री जी ने प्रदेश सरकार से इस सूखे के संबंध में कोई रिपोर्ट जरूर मांगी है और उस रिपोर्ट के आने के पश्चात् ही पैरा 3 में उसका उल्लेख भी किया गया है । मेरा स्पष्ट मत है कि क्योंकि हम लोग तो प्रायः घूमते भी हैं और पूरे प्रदेश के लोगों से हमारा संपर्क भी रहता है, यह जो दिया गया है कि

40 प्रतिशत क्षेत्र में सामान्य चावल का प्रतिरोपण हो चुका है और ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों की फसलों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। ज्वार और बाजरा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है हम स्वीकार करते हैं, बुरा प्रभाव से हमारा मतलब यह है कि बिल्कुल ही नष्ट हो गई है। मकई भी हमारे यहां होती है और मकई की फसल 1.19 मिलियन हेक्टेयर में होती है, उसकी कहीं चर्चा ही नहीं है और जबकि पूरे सूबे की फसल समाप्त हो गई है। चारा भी हमारे यहां काफी है क्योंकि हर प्रदेश में अगर चारा न रहे तो चारे की व्यवस्था करती पड़ती है। लेकिन जब पानी पड़ा ही नहीं है तो चारा भवेषियों के लिए कैसे प्राप्त होगा? उस नुकसान के संबंध में स्टेटमेंट में चर्चा नहीं की गई है। साथ-ही-साथ एक और बहुत ही गंभीर बात की ओर मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार को जो रिपोर्ट आई है, वह रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है बल्कि वास्तविकता के विरुद्ध है। यह क्यों वास्तविकता के विरुद्ध है, उसके कारण मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी एक प्रश्न और खड़ा हो रहा है कि आगे यदि पानी पड़ जाय तो ध्यान की रोपाई कैसे होगी और दूसरी फसल कैसे बोई जाएगी क्योंकि सीडलिस्स, जो धान का बीज दिया जाता है, वह तो सारे-का-सारा खेत में संपादित हो गया। वह तो कुछ है ही नहीं, इसलिए अगर वर्षा होगी, उससे धान की रोपाई हो सकती है, लेकिन अब धान की रोपाई का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि उसका बीज ही संपादित हो गया है। इसलिए मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस संबंध में प्रदेश सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगवाने का कष्ट करेंगे क्योंकि सही मायनों में सदन के सामने और प्रदेश की जनता के सामने यह बात आनी चाहिए कि प्रदेश सरकार ने क्यों वास्तविकता के विरुद्ध यह काम किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी भासादेकर) : यादव जी, आपका टाइम खत्म हो गया।

श्री राम नरेश यादव : महोदय, पैरा-7 में दिया है कि केन्द्रीय जल आयोग देश में 56 महत्वपूर्ण जलाशयों को मानीटर करता है फिर भी उत्तर प्रदेश और बिहार में इस समय जलाशयों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अब चूंकि आगे यह बहुत ही चिंता का विषय होने वाला है क्योंकि अभी पानी पड़ने के कोई संकेत नहीं है कि पानी पड़ ही जाएगा, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो जलाशय हैं उनमें जन में क्या स्थिति थी और उन जलाशयों में इस समय पानी के भंडारण की क्या स्थिति है। महोदय, यह चूंकि एक चिंता का विषय हो रहा है, इस बारे में आप विचार करें क्योंकि उससे यह समस्या भी दूर हो सकेगी और आपको भी बल मिल सकेगा प्रदेश सरकार को क्या-क्या निर्देश दिए जाने हैं? साथ ही चूंकि जबकि यह इतना बड़ा मामला हो गया है और प्रदेश सरकारों को आपने निर्देश दिया है तो यह भी रिपोर्ट आपको होगी कि बिजली की क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, इनपुट्स की क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? इसलिए जबकि केन्द्रीय सरकार उसकी मानीटरिंग करती है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में सूखा हुआ है तो क्या आप उस मानीटरिंग के साथ अपनी ओर से कोई टीम उत्तर प्रदेश में भेजेंगे जोकि वहां अधिकारियों के साथ बैठकर जो नुकसान हुआ है, पूरी उसकी समीक्षा कर सके और समीक्षा करने के बाद केन्द्र सरकार पुनः कोई निर्देश देने का कष्ट करेगी?

महोदय, पैरा-11 में दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो प्राकृतिक आपदा राहत कोष है, उसमें 75 फीसदी सेंट्रल गवर्नमेंट का है और बाकी पैसा राज्य सरकारों का है। इस सिलसिले में मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो कांटा होना चाहिए, वह उसने रखा है या नहीं? अगर रखा है तो उसका किस तरह से उपयोग हो रहा है? क्या आप उसके उपयोग के बारे में भी अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर वहां से जानकारी मांगकर सदन की अवगत कराने का काम करेंगे? यह भी मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[श्री रम नरेश यादव]

महोदय, यह बात भी सही है कि जहाँ पर सूखा पड़ेगा तो गन्ने की फसल तो सूखेगी ही, कोटाणु लगेगी ही और ये सारी चीजें होंगी। सारे प्रदेश की गन्ने की फसल बढ़ाई हो रही है, लेकिन जो कुछ रह गई है, उसे बचाने के लिए केन्द्र सरकार क्या कोशिश कर रही है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है और अगर हमारी फसल का नुकसान होता है, क्षति होती है तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। इस संयंत्र में केन्द्रीय सरकार की क्या योजना है, क्या कदम उठाने जा रहे हैं? इस संबंध में भी माननीय मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to ask the hon'ble Minister certain questions with regard to his statement which he has made in this House and which is, no doubt, a detailed statement and a painstaking statement and it is made after elaborate consideration of the situation resulting from near-failure of monsoon in the country. But certain question remain to be asked with a view to move the hon'ble Minister to consider certain aspects of the matter. -Firstly, it is submitted that in the entire statement it appears that the hon'ble Minister's attention has not been drawn to the conditions prevalent in the State of Jammu and Kashmir. In the State of Jammu and Kashmir the entire Jammu division is fed by monsoon just as Punjab, Uttar Pradesh or, Bihar. But monsoon has failed. The result is that in all the *kandy* area of Jammu region the crops have failed. There is no fodder. There is near-famine condition. I would, therefore, request the hon'ble Minister to apply his mind to that side of the country as well and to take steps so that the lot of the people can be ameliorated. In Kashmir the areas which are lying on height 'such' as *kandy* area are also fed by rain water. These are *barami* lands. *Barami* needs rain, but rain has not come. So, the people living there such as Nomads, Gujjars and Gaddis are suffering for want of all these

and the hon'ble Minister will do well in these bad days through which we are passing to see that the difficulties of the people are removed, and turn his kind attention to those who are suffering from possible famine.

Secondly, I would like to request the hon'ble Minister to find out whether any programme such as food-for-work programme can be undertaken in areas where he finds that as a result of this natural calamity the crop has failed. The hon'ble Minister may kindly see what the foodgrains available are with the Food Corporation of India and that is an enterprise which has got ample foodgrains with it and, I think, the hon'ble Minister can tap that Corporation for the purpose of ameliorating the condition of the people who are affected by the failure of rain. For that reason the food-for-work programme may be undertaken, that is to say whatever works are to be done in those areas may be got done by the people and they may be paid in return for their work in foodgrains.

Last but not the least, the hon'ble Minister has said in para-10 that as early as in April 1991 the Ministry of Agriculture had written to the State Agriculture Production Commissioners suggesting Model Contingency Crop Plans to meet the adverse situation. That means the Central Government had risen to the occasion well in time. But I would like the hon'ble Minister to make us aware what the reaction was of the States which were approached and which were told that they should evolve Model Contingency Crop Plans to meet such a situation as and when it arose. With these words I thank the hon'ble Minister for making this statement and I hope he will consider our lot also.

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) :
उपसभाध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जी से जैसे बयान की आशा थी वैसे वह नहीं है। वह मंत्री भी हैं, लेकिन हमसे पहले किसान नेता हैं और उनके बयान में मझे कोई बात पले नहीं पड़ी, मुझ क्षमा करेंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक ही बात अपने जिले के बारे में कहूंगा। मेरठ जनपद में, जहाँ मंत्रीजी गए भी हैं, एक क्षेत्र है चौगावा, यह द्वितीय विकासखंड में पड़ता है, वहाँ पर सामान्यतः जो वाटर लेवल है 60 फीट का है और अब जब सूखा पड़ रहा है पानी का नाम नहीं है तो वाटर लेवल और नीचे चला गया है। यहाँ तक कि जो बड़े सरकारी ट्यूबवेल हैं, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया है, नहर वहाँ बिल्कुल नहीं है और ट्यूबवेल काम नहीं कर रहा, प्राइवेट नहीं सरकारी मैं कह रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि प्रादेशिक सरकार क्या कर रही है, एक तो यह रिपोर्ट आप मंगायें? और श्रोमान्, अगर वह कुछ नहीं कर रही है या काम कर रही है या पैसे की कमी है—यह बहुत बड़ा क्षेत्र है और बड़े मेहनती किसानों का है और इसमें कम से कम 50 गांव हैं, इस क्षेत्र में कम से कम पानी की व्यवस्था नहर की या और किसी किसम के ट्यूबवेल की, मैं नहीं जानता कि जहाँ इतना गहरा पानी हो वहाँ कोई और टैक्नीक हो सकती है, ऐसी कोई व्यवस्था राज्य सरकार से मिलकर आप अपने स्तर पर करा सकेंगे? यह बड़े संतोष की बात होगी वहाँ के लोगों के लिए और देश के लिए।

एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि सूखे में किसानों की क्या हालत है, यह आपकी रिपोर्ट में नहीं है। कहता हूँ कि लाहिल्लाहि मची हुई है और आपने जो फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ाए हैं उसने किसानों की कमर और तोड़ दी है। तो क्या किसानों को राहत देने के लिए गन्ने का भाव जो आप तय करेंगे, जिस पर आप विचार कर रहे होंगे, क्या गन्ने का भाव, सूखे की वजह से राहत देने के लिए, 50 रुपये प्रति क्विंटल तय करने के लिए आप विचार करेंगे? यह आप स्पष्ट करें, साफ, साफ। आप किसान हैं।

श्री महेंद्र सिंह लाठर (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से दो चर-बर्तें पूछना चाहूँ। चेयरमैन सहेब, हमारे देश की बड़ी बदकिस्मती है कि हमें आजाद हुए 44 साल हो गए

हैं लेकिन अभी तक हमारी कोई नेशनल पालिसी इस बारे में नहीं बनी है। दो दिन पहले भारत सरकार के मंत्री ने फ्लड के बारे में स्टेटमेंट दिया था कि फ्लड की वजह से इतने किसानों का नुकसान हो गया और कल पि मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि सूखे की वजह से इतना नुकसान हो गया। यह जानना चाहूँगा मंत्री महोदय से कि क्या कोई ऐसा इंतजाम सरकार नहीं कर सकती कि जो ज्यादा पानी से नुकसान होता है, जो फ्लड का पानी होता है, क्या उसको कंट्रोल करके, उसको स्टोर करके, जहाँ पर सूखा पड़ता है, उस पानी का इस्तेमाल उस इलाके में किया जाए ताकि जो बाढ़ से नुकसान होता है वह भी न हो और जो सूखे से नुकसान होता है वह भी न हो? मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए यह कोई मुश्किल बात नहीं है और कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी या कमीशन ऐसा बनाना चाहिए। कहीं पर कावेरी नदी का झगड़ा हो रहा है, कहीं पर हमारे हरियाणा के अंदर जो पाकिस्तान से पानी खरीदा गया था हरियाणा और राजस्थान की जमीन को इरिगेट करने के लिए, वहाँ पर एम०वी० एल० कैनल करोड़ों रुपये लगकर हरियाणा में बनी पड़ी है लेकिन जो लिंक कैनल पंजाब में बननी है, वह नहीं बनी और जो पानी हमने पाकिस्तान से मोल लिया वह न हरियाणा की जमीन में लग रहा है, न राजस्थान की जमीन में लग रहा है और वह बेकार हो रहा है और फिर पाकिस्तान में जा रहा है, सरकार इस पर कोई गौर नहीं कर रही है। हमारे हरियाणा में, मंत्री महोदय ने पैरा 9 में लिखा है कि सिर्फ दो जिले इफेक्टिव हुए हैं, लेकिन चेयरमैन सहेब, सारा हरियाणा इफेक्टिव है। आज वहाँ पर इतना सूखा है कि सारी फसल सूख चकी है। हम वहाँ पर चक्कल पड़ा करते हैं जो एक्सपोर्ट होता है, फारेन एक्सचेंज कम कर लाया जाता है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। न वहाँ पर बिजली दी जा रही है, न वहाँ पर पानी दिया जा रहा है और आपके माध्यम से यह मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूँगा कि जो टेम्परेरी राइस शूट्स हरियाणा में दिए

[श्री महेन्द्र सिंह लाठर]

जाते थे चावल पैदा करने के लिए, इस दफा हरियाणा की सरकार ने वह टेम्परेरी राइस शूट्स नहीं दिए। तीसरे दिन बिजली दी जा रही है, मोटरें सड़ रही हैं, सब-सप्लाय वाटर लेवल नीचे चला गया है। अगर 5 हर्स पावर की मोटर से वह नहीं उठता और वहाँ पर कोई किसान अगर 8 हर्स पावर की मोटर लगाता है पानी उठाने के लिए तो उसका वहाँ पर चालान किया जाता है, पाँच-पाँच हजार रुपए का जमाना किया जाता है।

मैं एक बात और मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि किसान ने बीज भी डाल दिया, किसान ने खाद भी डाल दी, किसान ने मजदूरी भी लगा दी लेकिन वह फसल सूख चकी है सूखे की वजह से। क्या भारत सरकार इन किसानों को कोई कम्पेन्सेशन देने की बात करेगी जिनकी फसल को नुकसान हो चका है?

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, my first question is whether the Centre has sent any Central team for *assessing* to the draught-affected areas. The second question is whether, there was any Central assistance in the form of interim relief to any State. The third is whether there are any starvation deaths in any State. My fourth question is this in the coming days, there are going to be drinking water problem, cattle fodder problem, unemployment problem, etc., in the rural areas. The statement is totally evasive. It has thrown the entire burden on the States. I would like to know from the Minister whether the Central Government has started any anti-drought schemes and allotted any money to the Department of Rural Development to help, the States. Before and during the Gulf War, ecologists, scientists and environmentalists predicted that there would be some impact on the monsoons in India. I would like to know whether there is any -such impact on India. I come to my last question. The World-Watch Institute based in Washington has, in its report said that India will be facing famine condi-

tions in the ninetigs. It also stated that this is because of gross mismanagement, deforestation, denuding of trees and water-tables going down, etc. Has the Government gone through this report? These are the questions on which I seek the Minister's clarifications.

श्री मोहम्मद सजीम (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष जी, आजादी के 44 साल बाद भी—अल्लह मेव दे, पानी दे, वृष्टि दे, ऐसा हमारे मंत्री जी के वधान से पता चलता कि अगर बारिश ठीक हो गई तो सब ठीक है वरना हम परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो मैं जो सबल पूछना चाहता हूँ वह यह है जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन जिसका नतीजा उसे भगतना पड़ता है, वह यह है कि बड़े-बड़े हमारे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, वर्षों से वे पेंडिंग रहते हैं—क्लियरेंस नहीं, फंड एलोटमेंट नहीं, उस मामले में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही खुद जरा कोशिश करके जैसे बहुत से स्टेट से यह मांग उठती रहती है, तो हमारे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं उसके लिए कोशिश एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कर रही है या नहीं?

दूसरा है कि स्मॉल एंड मीडियम, इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। उस मामले में भी जो स्टेट में है, बहुत से स्टेट में यह काम करके सूखा का जो असर है उसको टाला जा सका है। मैं बंगाल से आया हूँ। मैं कह सकता हूँ। अभी हमारे दूसरे साथी भी कह रहे थे, कि वर्षा का पानी को स्टोर करके बाद में उसको सूखा मौसम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्षों से ऐसे बहुत से टैंक हैं जिनको नार्थ इंडिया में भी कई जगहों पर हम लोग देखते हैं, जिसमें वर्षों से सिल्ट जम गये हैं अतः उसको डिर्सिल्टिंग करके वहाँ पानी स्टोर करने का बंदोबस्त किया जाये और जहाँ नहीं हैं वहाँ यह ग्रामीण कर्मसंस्थान योजना के द्वारा जैसे जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कुछ एम्प्लायमेंट का बंदोबस्त गाँवों में किया जा रहा है, तो उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं ताकि गाँव के जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें लगा कर

सूखा मौसम में बड़े-बड़े ट्रैक खोद सकते हैं ताकि बाद में उसमें हम मानसून में पानी स्टोर कर सकते हैं।

जैसा स्टेटमेंट में बताया गया है कि जो खेती का काम है वह बहुत कम हुआ है। तो इसके लिये किसानों को जो माभला है उसको नजर दिया जायेगा, ऐसा मंत्री जी ने बताया और उसमें एग्योरेंस भी दिया है। लेकिन जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं जिनको इस सूखा मौसम में कोई काम मिल नहीं रहा है, क्योंकि खेत में कोई काम मिल नहीं रहा है—क्योंकि खेत में काम ही नहीं तो क्या उसके लिए कोई विशेष प्रबंध किया जा सकता है, यह मंत्री महोदय जरा बतायेंगे।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारा प्रदेश सूखे से बुरी तरह ग्रस्त है। महोदय, पहले जहाँ पर किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते थे, वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार बी.डी.ओ. के माध्यम से फ्री बोरिंग कराती थी और नलकूप के लिए डीजल इंजन हेतु पैसा उपलब्ध कराती थी, कर्ज के रूप में, जो बैंकों से दिया जाता था। महोदय, कुछ समय से, मैंने ख्याल से पिछले एक माह या दो माह से यह लोन की व्यवस्था और बोरिंग की व्यवस्था बिल्कुल बंद हो गई है, जब कि सूखे से किसानों की हालत इतनी खराब हो रही है। महोदय, इस तरह किसानों पर दोहरी भार पड़ रही है। तो मैं चाहूँगी कि इस व्यवस्था को दोबारा शुरू कराया जाए।

महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि केन्द्रीय जल आयोग 56 जलाशयों का मॉनिटरिंग करता है। मैं जानना चाहूँगी कि क्या प्रदेश सरकारें संकटकालीन व्यवस्था के लिए कुछ जलाशयों की मॉनिटरिंग करके किसानों को ऐसे वक्त में पानी उपलब्ध कराने का काम नहीं कर सकती हैं?

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं एक ही मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के पैरा 8 में यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में केवल 40 प्रतिशत धान का प्रतिरोपण हुआ है। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि मंत्री जी का यह ध्यान गलत है लेकिन मैं निवेदन करूँगा कि फिर से इसका सर्वेक्षण करवा जाए। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हम जानते हैं कि वहाँ 10 प्रतिशत भी धान की रोपाई नहीं हुई है और खरीफ की जो फसलें हैं ज्वार, बाजरा, ये तो बिल्कुल जल गई हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह बात कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और स्वयं सरकार की ओर से कल लोकसभा में यह स्वीकार किया गया कि देश में 23,76,70,000 लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं जिनमें सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के हैं। तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में सूखा राहत के लिए कितना धन सरकार की ओर से आवंटित किया गया है?

महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहती हूँ कि सरकार सस्ते गल्ले की दुकान खोलने के लिए क्या प्रावधान कर रही है? मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूँगा कि वे उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति के बारे में मॉनिटरिंग कराएँ क्योंकि वहाँ की सरकार जो है उसको तो सूखे का ज्ञान नहीं है। वह तो राम मंदिर बनवाने के चक्कर में हैं। किसानों से उनकी कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश में जो भयंकर सूखा पड़ा है, उसकी मॉनिटरिंग कराएगी?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR):
Now, Mr. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Thank you very mach, Mr. Vice-Chairman, Sir. I will put only pointed questions.

Sir, it has been admitted by the honourable Minister of Agriculture that

[Shri V. Narayanasamy]

the monsoon has not actually reached *Delhi* and other places in, the northern (part of the country and there has not been sufficient rainfall in this region. Sir, the Minister has much experience so far as agriculture is concerned and he may be knowing one thing. Whenever there is a heavy downpour, the water goes into the sea. By digging bore wells the water can be stored in the underground so that it can be used for irrigation purposes by the farmers. We can use that water by retapping it. This system which was introduced has not been implemented in many States. I would like to know what is being done in this regard.

Secondly, the loss of crops due to the drought conditions prevailing in the western part of the country has not been assessed and the statement does not say anything about it. I would like to know what the actual loss is and also, loss in terms of money. I would like to know what the estimate is in this regard.

Thirdly, there has been pre-monsoon showers in some areas in Tamil Nadu and in my area, Pondicherry. But, in the southern part of Tamil Nadu, this has not taken place. I would like to know whether the Central Team visited the drought-affected areas and assessed the situation there in order to help the States concerned. I would like to have clarifications on these • points. Thank you, Sir-.

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : पिछे एक सवाल मे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूखा जबरदस्त है। कुएं भी सूख गए हैं, जमीन भी सूख गई है। खाने के साथ पानी भी सूख गया है। शायद आपके ध्यान में होगा कि जब इस तरह का सूखा सन् 1980 में आया तो अन्न के बढ़ने काम की योजना चलाई गई थी। उसमे लोगों का इतना पेट भरा था कि जितना भरे मौसम में भी नहीं भरा।

श्री राम नरेश यादव : जरा करेक्ट कर लीजिए। यह 1977 में हुआ था।

श्री अनन्त राम जायसवाल : रामनरेश जी उस समय मुख्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उस वक़्त लोगों का इतना पेट भरा था कि रेकार्ड यह बतला रहे हैं कि लोगों की तंदुरस्ती में भी सुधार हुआ था। उस योजना को चलाने में क्या भारत सरकार को कोई आपत्ति है? अगर नहीं है तो क्या उसको तुरन्त लागू किया जाएगा?

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Sir, with your kind permission I want to ask one question. There is a difference in giving the Central assistance in the case of floods and drought. When ever we ask the question, the Ministry says that these are the norms fixed by the Finance Commission. So, I request the hon. Minister to move the Finance 'Commission' that both are natural calamities and in.....

SHRI V. NARAYANASAMY: Drought is more serious.

SHRI H. HANUMANTHAPPA:

• getting the Central assistance, floods and draught should not be discriminated. The norms of assistance should be changed. So, I request the Minister to move the Finance Commission highlighting the calamities as well as the sufferings of the people in the case of floods as well as drought and find an equitable solution for both.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You have a dynamic Minister. He will do everything.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Every-time the Ministry answers that these are the norms fixed by the Finance Commission. Actually, the Ministry has to move the Finance Commission.

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Sir, I support Mr. Hanumanthappa,

श्री बनाराम जाखड़ : माननीय उप-सभापति जी, माननीय सदस्यों के जो प्रश्न हैं, वह तक्रारों के सारे के सारे उत्तर मैंने

दे दिए हैं। कुछ थोड़े से सवाल उत्पन्न होते हैं, उनके विषय में कुछ कहना चाहूंगा जैसे बिहार के मुतल्लिक माननीय सदस्या ने कहा सोन कैनल के बारे में। मैं आपको बात को इरिगेशन मिनिसट्री तक पहुंचा दूंगा लेकिन यह ज्यादा काम स्टेट सरकार का है। प्रदेश सरकार अगर चाहे और उसे चाहिए और डिसिल्टिंग कैनल की करनी चाहिए।

श्री 'न' कमला मिश्रा : डिसिल्टिंग की बात नहीं है। यह तीन प्रांतों की बात है। सोन सिस्टम से पानी रिलीज करने की बात है।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने कहा कि इरिगेशन मिनिसट्री तक आपको बात को पहुंचा दूंगा, वह देख लेंगे।

जहां तक आपने पूछा कि डीजल और पावर नहीं है। बात सही है कि पावर के बिना कोई काम बनता नहीं है। देश की प्रगति करनी है तो पावर की बहुत आवश्यकता है। विशेषकर आपके प्रान्त में मैंने देखा कि बिजली का उत्पादन बहुत कम है। सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिए और यहां से भी ऊर्जा मंत्री जो के साथ बात करूंगा कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करें जिसमें उत्पादन बढ़ सके। जितना उत्पादन अधिक होगा उतनी ही उत्पादन भी अधिक होगी चाहे धान की हो, चाहे इंडस्ट्री की हो।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुतल्लिक आपने कहा, और साथियों ने भी कहा। मेरे पास अभी रिपोर्ट आई है प्रदेश सरकार की। उसमें उन्होंने लिखा है :

"According to the latest rainfall figures received from the Meteorological Office, Amausi, only 7 districts—Jhansi, Allahabad, Lalitpur, Muzaffarnagar, Meerut, Etah and Badaun—have received almost normal rainfall. Even in these districts the rainfall has not been evenly distributed. Eight districts of the State have received 60 to 80 per cent of the normal rainfall.

Another 10 districts are in the category of highly deficient as they received only 40 to 60 per cent of the normal rainfall. The position is very critical in the remaining 38 districts of the State where only scanty rain, below 40 per cent of the normal has been received."

जो आपने 40 परसेंट के मुतल्लिक बात की थी उसमें इन्होंने कहा है कि 36 परसेंट एरिया ही है। लेकिन जैसा आपने कहा है मीटिंग करनी चाहिये...

श्री राम नरेश यादव : अभी जो रिपोर्ट आयी है वह भी सही नहीं है। 64 जिलों में कम से कम 50 जिलों ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है।

श्री बलराम जाखड़ : जो आपने मीटिंग का सुझाव दिया था वह हमने 5 तारीख को रखा है। बिहार और वे सभी सूबाप्रान्त जो प्रदेश हैं उनकी मीटिंग यहां हो रही है। उसमें बातचीत करके हम देखेंगे।

दूसरे जो 24 घंटे सप्लाय का प्रश्न है वह तो स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड से है। उनको हम कहते रहते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा बिजली दें और जहां सूखा हो तो फसल बचाने के लिये इंडस्ट्रीज की बिजली काट कर इनको दी जाय। इसी के साथ कैनल सिस्ट क्लीयरेंस की बात है इसको स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिये। ये छोट-छोटे काम हैं इनको प्रदेश सरकार कर सकती है और करने चाहिये। हम उनको लिखेंगे। मेरे खयाल में जो आपके अपने प्रदेश के एम0एल0एज0 हैं उनसे हम को संपर्क करना चाहिये ताकि वे अपनी सरकार को कसते रहें। यह काम गंभीरता से होना चाहिये।

आपने मौसम विभाग के बारे में कहा था। यह बिल्कुल ठीक है कि प्रगति हर क्षेत्र में हो। वैसे मौसम विभाग पहले से काफी अच्छा है। अब तक

[श्री बलराम जाखड़]

तकरीबन तकरीबन जो भविष्यवाणी की हुई है वह ठीक-ठीक चल रही है। काफी हमारे पास साधन हैं जिससे हम जान सकते हैं कि क्या-क्या कब-कब हो रहा है। उसके जानने से फायदा पहुंचता है और उसके बाद उसकी तैयारी की जाती है। इसलिये हमने मई के महीने में बुलाकर बात की थी कि आप आइये, हम से बात करिये कि किस तरह से हम इसका निराकरण कर सकते हैं, आने वाली विपत्ति कैसे ठीक हो सकती है।

कम्पनसेशन की बात की थी। सर्वे टीम भेजने की बात काफी मैसे सदस्यों ने की कि आप अपनी सर्वे टीम भेजिये। वह देख कर काम करें कि किस प्रकार से नुकसान हुआ है और उसका क्या करना चाहिये। इसके मुतलिक अगर आपने मेरा बयान ध्यान से पढ़ा होता तो यह दिक्कत नहीं आती। इसमें हमारी कुछ वदिश आ गई है। पहले तो सर्वे टीम सेंटर की तरफ से भेजते थे जब भी कोई ऐसा क्लेमिटी हो जाती थी नेचुरल प्राकृतिक विपत्ति आ जाती थी तो यहां से टीम जाती थी। देखते थे, सर्वे करते थे और फिर आपस में बात-चीत होती थी, अनुदान यहां से जाता था। लेकिन मुसीबत लोगों को महसूस हुई और स्टेट गवर्नमेंट ने इस के लिये आपत्ति उठाई। यह कहा कि पैसा हमारा है यह चौधरी क्यों बन बैठे। हमारा पैसा हमें ही दे दो। नाइन्थ फाइनैस कमीशन में लिखा है।

"The primary responsibility of managing natural calamities is that of the State Governments. Emphasizing this principle, the IX Finance Commission recommended ready access to resources and autonomy in relief operations for the States. On the recommendations of the IX Finance Commission, from 1st April 1990, a Calamity Relief Fund (CRF) for financing relief expenditure, has been constituted for each State, 75

per cent of which is contributed by the Central Government and the balance by the State Government concerned. An annual contribution of Rs. 804 crores for the State CRPFs has been envisaged for, and of this amount Rs. 603 crores are contributed by the Central Government. Fifty per cent of the Central share of the CRF for the year 1991-92 has already been released to States. The State level Committee, headed by the Chief Secretary of the State, is empowered to decide on all matters connected with the financing of the relief expenditure, including norms of assistance. The State Governments are required to meet all expenditure on relief operations from the CRF.*"

और कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। अगर वह हमसे पहले भी मांगते हैं कि हमें एक किण्ट रिलीज दार दो तो हमने दो किण्टे रिलीज की हैं। यू०पी० का उदाहरण देता हूं। आपने मुझ से पूछा है...

श्री राम नरेश यादव : जो रिलीफ वर्क है वह तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी लेकिन सचमुच कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में तो आप करा सकते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : वह हमारे पास नहीं रखा। टीम हम सर्वे की तभी भेजते जब हमारे पास होता। मैं आपको बताऊ पिछले साल हमने 90 करोड़ रुपया यू०पी० को देना था। उसमें से 28.92 करोड़, 29 करोड़ सभ्य लीजिये यू०पी० ने खर्च किया है। उसमें से 60 करोड़ रुपय बचा हुआ है। 90 करोड़ इस साल का है तो अभी उनके पास 150 करोड़ रुपये बचा है जिसको वे खर्च कर सकते हैं अगर कोई नेचुरल क्लेमिटी आती है तो।

श्री ईश दत्त यादव : इस साल कितना दिया ?

श्री बलराम जाखड़ : हमारे पास जितना रिजर्व होता है किण्टी में दे देते

हैं। हमने दो किश्ते रिलीज कर दी हैं यानी 50 परसेंट रिलीज कर दिया है। और अगर आवश्यकता हो तो वे हमसे और किश्तें भी मांग सकते हैं और हम अगले साल की किश्त भी दे सकते हैं। ऐसी कोई डिमांड हो जाय, ऐसी कोई विपत्ति आ जाय जिसको सभाला नहीं जा सकता है तो सहायता दी जा सकती है। कोई नेशनल क्लेमिटी, राष्ट्रीय किस्म की विपत्ति घोषित हो जाय उसके लिये सेंटर एक टीम भेज सकता है। यह एक नई चीज है और उसमें आपस में बात हो सकती है।

आपने जम्मू-कश्मीर की बात की है। उसको इसमें रखा नहीं गया है। जम्मू-काश्मीर भी एक डेफिसिट एरिया है। वहां बरसात नहीं हुई है। उसकी भी हमें चिंता है। खाने-पीने के मुत्तलिक आप चिंता न कीजिये। भगवान की कृपा से हमारे पास पूर्ण भंडार है और हमारे पास 19 मिलियन टन का अनाज है। उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप जितना भी कहेंगे उसको हम पूरा कर देंगे। मेरे पास आंकड़े हैं। इसमें कुछ विरोधाभास है। यू.पी. का 20.60 परसेंट धान का रोपण हुआ है। पिछले साल नार्मल 51 परसेंट था और लास्ट ईयर 41 परसेंट था। मेज का 50.9 परसेंट है और नार्मल 11.32 था। लास्ट ईयर 6.81 परसेंट था और बाजरे का 1.17 परसेंट है और नार्मल 8.33 है। लास्ट ईयर 2.50 था। बिहार में गोईय 11.37 है और पहले यह 51 परसेंट था और लास्ट ईयर 36 परसेंट था। मेज का 40.52 परसेंट था और नार्मल 60.84 परसेंट है और पिछले साल 5.5 परसेंट था। बाजरे का 1.95 परसेंट है और नार्मल 2.5 परसेंट है और पिछले साल 2.25 था। इस प्रकार से सारी बातें हैं। एक माननीय सदस्य ने रिजरवोयर्स के बारे में पूछा।

श्री महेश्वर सिंह लाठर : बाढ़ के बारे में क्या कोई नेशनल पालिसी भी है?

श्री बलराम जाखड़ : यह मसला इरी गेशन डिपार्टमेंट के पास है। वैसे तो मेरे दिमाग में ये चीजें जुड़ी रहती हैं और मैं इस संबंध में काम भी करता रहता हूँ। मैं इस संबंध में बता सकता हूँ। लेकिन करना उनको ही है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जल्दी क्यों नहीं होता है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी होना चाहिये। जितनी देर होती है उसी हिसाब से खर्चा भी बढ़ जाता है और नुकसान भी होता है। इसलिये सोचना पड़ता है। आप जानते हैं कि जितना कपड़ा होता है, कोट भी उसी हिसाब से बनता है। असल मसला फाइनेंस का है। उनका गैस्टेशन पोस्टिवड लंबा होत है। आपने कहा कि पाकिस्तान में पानी जा रहा है। हम थर्ड डैम बना रहे हैं। पोंग और भाखड़ा डैम हमने बनाये हैं। मैं उस समय सिचाई मंत्री था। मेरी देखरेख में पोंग डैम बना। उसमें कितना टाइम लगता है और उत्पादन कितना होता है, यह मैं जानता हूँ।

श्री महेश्वर सिंह लाठर : एस० वाई० कौनल के बारे में क्या स्थिति है?

श्री बलराम जाखड़ : एस० वाई० कौनल का मेरे साथ संबंध नहीं है। वह दूसरा महकमा है और वही इस बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार से माननीय सदस्यों ने जितने भी सुझाव दिये हैं मैं उनका ध्यान रखूंगा।

श्री छोट मोई पटेल : 40 परसेंट फर्टि लाजर में जो सबसीडी है उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री बलराम जाखड़ : इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। सारी बात चल रही है, क्या होगा और क्या नहीं होगा, सारी आगे-पीछे की बातें देखनी पड़ती हैं। देश के हित में क्या है और किसानों के हित में क्या है, यह देखना पड़ता है। किसानों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसानों का ध्यान नहीं करेंगे तो देश का ध्यान कौन करेगा। देश को अगर सम्मान, आत्मविश्वास और आत्म-

[श्री बलराज जाखड़]

निर्भरता दी है तो वह किसान ने दी है। जब हम 34 करोड़ थे तो लाखों टन अनाज बाहर से मंगाया जाता था और आज हम 85 करोड़ हो गये हैं, तो भी आत्म निर्भर हैं। यह किसान की देन है। इस समय जो कुछ किया जा रहा है वह किसी विपत्ति के आधार पर किया जा रहा है। हम सोच रहे हैं और उसका निराकरण आप और हम मिलकर करेंगे तभी बात बनेगी।

श्रीमती कमला सिन्हा : मैंने एक प्रश्न पूछा था कि अभी बिजली का उत्पादन दो-चार दिन में तो हो नहीं सकता है। इसलिए सोन सिस्टम से, सिंगरीली से और उत्तर प्रदेश से क्या 15 सौ मैगावाट बिजली बिहार को दी जाएगी ?

श्री बलराम जाखड़ : इस बारे में तो ऊर्जा मंत्री बता सकते हैं। मैं अनाधिकार चेष्टा करूंगा तो वह अच्छा नहीं लगता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप ऊर्जा मंत्री तक इस बात को पहुंचा दीजिये।

श्री बलराम जाखड़ : वह भी पहुंचा दूंगा।

श्रीमती कमला सिन्हा : इस गम्भीर स्थिति को देखते हुए आप ऊर्जा मंत्री को कह तो सकते हैं कि वह तुरंत कार्रवाई करें।

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपकी बात को उन तक पहुंचा दूंगा।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इतने साधन हैं और अगर आप चेष्टा करें, अगर हममें भावना बढ जाय काम करने की, दत्तचित्त होकर, देशभक्ति के साथ अगर काम किया जाय तो बिहार एक ऐसा प्रांत है जो सब को अनाज दे सकता है, यह मेरी धारणा है। मैं बार बार वहां गया हूँ, मैंने देखा है, जमीन के साथ मेरा लगाव है, मैं जानता हूँ कि कैसे किया जा सकता है। सिर्फ करने की हिम्मत हो। आप सारे लोग बैठें। अगर नक्शा बदलना है तो प्रारूप बदल जायेगा और वहां एक नई बहार आ जायेगी।

श्री राम अवधेश सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या कमला सिन्हा जी ने जो कहा उनको जरा दूसरे ढंग से कहना चाहता हूँ। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि रिहंद डाम से बिजली चली जाती है बंबई को और वहां से चली जाती है पंजाब को...

श्री बलराम जाखड़ : राम अवधेश जी इससे मेरा संबंध नहीं है।

श्री राम अवधेश सिंह : गवर्नमेंट की कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी होती है, हम इस बात को मानते हैं। इसलिये आप हमारी इस बात को पहुंचा दें जो बिहार को सूखे के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।... (व्यवधान)...

श्री बलराम जाखड़ : आप कहे बिगाड़ी से बंबई जाना है और कलकत्ता चले जाय, इससे बात तो नहीं बनेगी। अगर आप सजेशन देंगे तो हम आपकी बात को वहां तक पहुंचा देंगे।

श्री राम अवधेश सिंह : पंजाब को बिजली जायेगी और हमारे पानी से वह बिजली बनेगी लेकिन हमको वह बिजली नहीं मिलेगी, इससे बढ़कर घोर अन्याय क्या होगा ?

श्री बलराम जाखड़ : देश में पैदा होने वाली सारी बिजली और यह सारा देश आपका है और इसका वितरण आपकी ही सरकार और आप हो करते हैं। कभी आप होते हैं और कभी और होता है। (व्यवधान) इस धारणा से यह देश अवन्नति कर रहा है कि यह मेरा है। यह मेरा नहीं बल्कि हमारा सब का है। हमें इस भावना को जाग्रत करना है कि यह हमारा देश है। कोई पंजाबी हिन्दुस्तानी नहीं बनना चाहता यह क्या तमाशा है।... (व्यवधान)...

शांति त्यागी जी ने कहा कि पानी नीचे चला गया है। तो इसके लिये भी यही है कि वहां की सरकार को हम लिख सकते हैं। 5 तारीख को वे लोग आ रहे हैं। आप इस बारे में अगर थोड़ा सा आवेदन लिखकर देंगे तो मैं उनको वह दे दूंगा क्योंकि यह मामला प्रदेश सरकारों के अन्तर्गत आता है।

अगर हम बीच में पड़ेगे तो वे कहेंगे कि अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं और सेंटर हमारे मामलों में दखल दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच आपस में सामंजस्य पैदा हो और आपस में मिलकर, सहकारिता के आधार पर हम काम करें।

श्री महेंद्र सिंह लाठर : गन्ने के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री बलराम जाखड़ : गन्ने का बता रहा हूँ वह सरल डेवलपमेंट में आयगा। मैं उनको बता दूंगा, सरल डेवलपमेंट के बारे में, जवाहर योजना के मुक्तिक जो है, वैसे ही उस के मुक्तिक बात है। गन्ने का, अनाज का, सारी बात जो मैंने बताई वह मैं बता दूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि मैं किसान के हितों के लिये दत्तचित्त हूँ। मैंने सारी जिदगी इसमें खर्च कर दी। न मुझे व्यापार आता है और न कुछ किया है। मैंने खेती की है, खुरपा चलाया है और अन्न का उत्पादन किया है, बूटे लगाये हैं। . . (व्यवधान) . . वह भी मेरे दिमाग में है लेकिन हो सकता है कि दृष्टिकोण में अंतर हो। लेकिन मैं किसान को किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचाना चाहता हूँ। मैंने यह बात वित्त

मंत्री से की है और वित्त मंत्री को सदन में यह दो बार कहलवाया है कि किसानों की हितों की रक्षा की जायेगी। जिस भी तरह हो उसके हितों की रक्षा की ही जानी चाहिये क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि किसानों के बगैर हमारा देश नहीं चल सकता है, हम चल नहीं सकते।

तो मैं आपसे कह रहा था कि शूगर का ही नहीं, अनाज का भी, कपास का भी, सारा कुछ जो है मेरे पास उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसको हम देख रहे हैं कि किस तरह हमको किसान का घर पूरा करना है, उसके लिये भी करना है और जिनके पास नहीं है उनका घर भी कैसे पूरा करना है, तो सारी बातें हमारे विचाराधीन हैं। आपके हितों की रक्षा के लिये मेरे से जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The House is adjourned till 11 a.m. on Monday, the 5th August.

The House then adjourned at twenty-five minutes past six of the clock till eleven of the clock on Monday the 5th August 1991.